



पीएम राहत कोष में अक्षय कुमार ने दिए 25 करोड़ रुपये >> 5

दैनिक जागरण

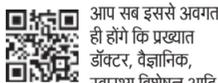


	विश्व	अमेरिका	इटली	भारत	(22 मार्च)	दिल्ली
कुल केस	6,22,157	1,05,726	86,498	972	352	49
मौतें	28,799	1,730	9,134	25	4	2
स्वस्थ हुए	1,37,364	2,538	10,950	83	23	5

भारत के प्रमुख राज्य			उत्तर प्रदेश	65	0
राज्य	केस	मौतें	राजस्थान	54	0
महाराष्ट्र	181	5	गुजरात	55	3
केरल	176	1	तमिलनाडु	41	1
तेलंगाना	65	1	अन्य	210	12
कर्नाटक	76	2	समय : रात 11:00 बजे तक		

अन्य प्रमुख देश		
देश	केस	मौतें
चीन	81,394	3,295
स्पेन	72,248	5,812
जर्मनी	53,340	399
ईरान	35,408	2,517

निश्चित रहें, पूरी तरह सुरक्षित है आपका अखबार



आप सब इससे अवगत ही होंगे कि प्रख्यात डॉक्टर, वैज्ञानिक, स्वास्थ्य विशेषज्ञ आदि बार-बार यह कह रहे हैं कि अखबारों से कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने का कोई खतरा नहीं है। आप पूरी तरह निश्चित होने के लिए इस कथुआ कोड को स्कैन करके खुद देख सकते हैं कि आपका प्रिय दैनिक जागरण समाचार पत्र कितने सुरक्षित तरीके से छपकर आपके हाथों में पहुंचता है। सतर्कता और सजगता की यह प्रक्रिया हम हर दिन-हर क्षण अपनाते हैं, क्योंकि आपकी तरह हम भी कोरोना को परास्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस प्रतिबद्धता को और प्रबल करने के लिए यह आवश्यक है कि आप समाचारों के सबसे विश्वसनीय स्रोत से जुड़े रहें। आपकी तरह हमें भी यह भरोसा है कि हम यह जग जीतेंगे।

हर प्रवासी मजदूर को मिलेगी मदद

फैसला ▶ परिस्थितियों की जटिलता को देखते हुए सभी जरूरतमंदों के रहने-खाने का होगा प्रबंध

पैदल ही घरों की ओर निकल पड़े लोगों को हाइवे किनारे ही दिया जाएगा आसरा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुविधाओं का इंतजाम करने को कहा। जो मजदूर अभी तक शहर से बाहर नहीं निकले हैं, उनके लिए भी समुचित प्रबंध करने को कहा गया है।

प्रचार के हर माध्यम से पहुंचाएंगे सूचना : प्रवासी मजदूरों तक सरकार की ओर से उनकी सहायता के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी नहीं पहुंचने और उनके बीच फैल रही अफवाहों को दूर करने के लिए केंद्र ने राज्य सरकारों को व्यापक प्रचार अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इसके लिए लाउडस्पीकर व अन्य माध्यमों के साथ-साथ एनजीओ और अन्य एजेंसियों को मदद दी जा सकती है। गृह सचिव ने साफ कर दिया कि लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।

फंड की कमी के कारण कुछ राज्यों की ओर से प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं देने की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का इस्तेमाल करने को कहा है। इस योजना में खासतौर पर लॉकडाउन के दौरान तीन महीने तक हर महीने प्रत्येक व्यक्ति को पांच किलो चावल या गेहूँ और एक परिवार को एक किलो दाल उपलब्ध करने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने राज्यों को प्रवासी मजदूरों पर आने वाले खर्च के लिए आपदा प्रबंधन फंड से धन निकालने की अनुमति भी दे दी है। गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्य सरकारों को प्रवासी मजदूरों के लिए आवश्यक कठिन चुनौतियों में से एक है। टाटा

बाल आयोग ने भी जताई चिंता पेज>>4



कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते राष्ट्रीय लॉकडाउन के बाद आनाक उभरे हालात के तहत दिल्ली-पनौती आर से प्रवासी श्रमिकों ने अपने सुदूर गांवों-घरों का रुख कर लिया है। बसें चलने की सूचना पर शनिवार को हजारों की संख्या में लोग कोशाबी-आनंद विहार बस अड्डे पर जुट गए और गंतव्य को रवाना हुए। इस दौरान भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को काफी मशकत करनी पड़ी। मनोज कुमार

हेल्पलाइन नंबर

कोरोना से जुड़ी सही जानकारी देने के लिए भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इन नंबरों को मोबाइल में सुरक्षित करके कोई भी प्रामाणिक सूचना पाई जा सकती है। कृपया नंबर दर्ज करके वाट्सएप पर सिर्फ नमस्कार का संदेश भेजें। तुरंत एक मैसेज आएगा, जिसके अनुसार वांछित जानकारी ली जा सकती है।

who: +41 7998931892
mygov: +919013151515

कोरोना को हराना है

कफ्यू में डील देने के खिलाफ लोग पहुंचे हाई कोर्ट

दवा के लिए सीडीआरआइ ने की अनुसंधान की पेशकश

घर-घर बनाए जा रहे मास्क, वितरण में जुटे सेवादाार

संडे बॉक्स

'कृष्ण' ने कहा, मैं इस भूमिका के लिए ही जन्मा

नई दिल्ली : टीवी धारावाहिक महाभारत के दूरदर्शन पर एक बार फिर प्रसारित होने पर कृष्ण, द्रोण, कर्ण, युधिष्ठिर, गांधारी और दुर्योधन की भूमिका निभाने वाले अभिनेताओं ने उस दौर की यादें साझा कीं। (पेज-10)

रविवार विशेष

सचमुच विश्व गुरु! भारतीय गवित, दुनिया चकित

लखनऊ : आज एक बार फिर भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा दुनिया कर रही है। जिस महापुरुष को लेकर हाहाकार मचा है, भारतीय ग्रंथों में हज़ारों वर्ष पूर्व इसकी भविष्यवाणी कर दी गई थी। (पेज-12)

कोरोना से जंग में टाटा ने दिए 1500 करोड़

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कोरोना वायरस के संक्रमण से पैदा हुए हालात से निपटने की मुहिम में टाटा संस और टाटा ट्रस्ट ने दरियादिली दिखाते हुए संयुक्त रूप से 1500 करोड़ रुपये की मदद का एलान किया है। इस धनराशि का उपयोग स्वास्थ्यकर्मियों और कोरोना वायरस से प्रभावितों के लिए आवश्यक मेडिकल सुर्क्षा उपकरण, जांच के लिए किट्स की खरीद और उपचार सुविधाओं की स्थापना के लिए किया जाएगा।

इस संबंध में जारी बयान में रतन टाटा ने कहा है, 'टाटा ट्रस्ट और टाटा समूह की कंपनियों पहले भी हमेशा जरूरत के वक्त देश के काम आई हैं। लेकिन कोरोना के आधिकारियों को मजबूत सारे संकटों से बड़ा है। मेरा मानना है कि इस असाधारण कठिन दौर में मानव प्रजाति के इतिहास की सबसे कठिन चुनौतियों में से एक है। टाटा

टाटा संस ने 1000 करोड़ और टाटा ट्रस्ट ने 500 करोड़ की मदद का किया एलान, रतन टाटा ने इस संकट को मानव प्रजाति के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया



रतन टाटा। फाइल

ट्रस्ट सभी प्रभावित समुदायों की सुरक्षा की शपथ के अनुसार चिकित्साकर्मियों को सुरक्षात्मक उपकरण, मरीजों के लिए श्वसन प्रणालियाँ एवं जांच किट खरीदने, संक्रमित रोगियों के लिए माडुलर उपचार सुविधाओं की स्थापना तथा स्वास्थ्यकर्मियों एवं पीड़ितों के ज्ञान प्रबंधन एवं प्रशिक्षण की खातिर 500 करोड़ रुपये के योगदान की घोषणा

करता है।

रतन टाटा ने कहा कि टाटा ट्रस्ट, टाटा संस तथा टाटा ग्रुप की कंपनियों अपने समर्पित देशी-विदेशी साझेदारों तथा सरकारों के साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ संयुक्त रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य की लड़ाई लड़ेंगी तथा समाज के सभी वर्गों और कमजोर तबकों तक पहुंचने का प्रयास करेंगी।

वहीं, टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखर ने कहा कि टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा, 'टाटा ट्रस्ट द्वारा की गई पहल के अलावा, हम आवश्यक वॉलेटर भी ला रहे हैं और भारत में भी जल्द ही इसका निर्माण करने के लिए काम कर रहे हैं। देश एक गंभीर स्थिति और संकट का सामना कर रहा है। हम जिन समुदायों की सेवा करते हैं, उनके जीवन को बचाने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं, हमें करना होगा।'

बाहर से आ रहे किसी को नहीं घुसने देंगे बिहार में : नीतीश

जेएनएन, नई दिल्ली

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए शुरू हुए लॉकडाउन के बाद पलायन से विषम परिस्थिति पैदा हो गई हैं। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी यात्री को लेकर आ रहे वाहन को बिहार की सीमा पर रोक दिया जाएगा। नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि ऐसे तो लॉकडाउन ही फेल हो जाएगा। वहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए बिहार में प्रवेश करने वाले वाहनों को रोक दिया जाएगा। नीतीश कुमार ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।

फंड की कमी के कारण कुछ राज्यों की ओर से प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं देने की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का इस्तेमाल करने को कहा है। इस योजना में खासतौर पर लॉकडाउन के दौरान तीन महीने तक हर महीने प्रत्येक व्यक्ति को पांच किलो चावल या गेहूँ और एक परिवार को एक किलो दाल उपलब्ध करने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने राज्यों को प्रवासी मजदूरों पर आने वाले खर्च के लिए आपदा प्रबंधन फंड से धन निकालने की अनुमति भी दे दी है। गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्य सरकारों को प्रवासी मजदूरों के लिए आवश्यक कठिन चुनौतियों में से एक है। टाटा

बता दें कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से पैदल ही अपने

गांव की ओर निकल पड़े लोगों को मदद के लिए बसें रवाना कर दी गईं। नोएडा और गाजियाबाद से बिहार के लिए बसें चल पड़ी हैं। इस सूचना के बाद नीतीश कुमार ने उच्चस्तरीय बैठक कर सीमा पर वाहनों को सीमा पर रोकने और यात्रियों के लिए आपदा राहत शिविर लगाए जाने का फैसला किया है।

ऐसे में अब झारखंड, बंगाल और यूपी की सीमा से भी कोई वाहन बिहार में अंदर नहीं आ सकेगा। यात्रियों को सीमा पर ही उतार कर भोजन, आवास और चिकित्सा आदि की पूरी व्यवस्था रहेगी। मुख्यमंत्री स्वयं इसकी मॉनीटरिंग कर रहे हैं। शिविर में बच्चों के लिए भी इंतजाम किए जा रहे। कम्प्यूटरी किचन चलाया जा सकता है।

बिहार के सीएम ने कहा- ऐसे होगा पलायन से तो फेल हो जाएगा लॉकडाउन



नीतीश कुमार। फाइल

उत्तर प्रदेश में भी एक लाख लोगों का होगा व्वाइरटाइन

बाहर से आए एक लाख लोगों को व्वाइरटाइन में रखना उठा : कोरोना संक्रमण से सजग उत्तर प्रदेश सरकार को नजर लगातार उन लोगों पर है, जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि बुधवार से लेकर शुक्रवार तक प्रदेश में करीब एक लाख लोगों को निगरानी रखने के साथ इन्हें अनिवार्य रूप से व्वाइरटाइन में रखा जाए। इसके साथ ही जनता की सुरक्षा, सुविधा और स्वास्थ्य के लिए गठित समितियों की समीक्षा में उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भ्रूखा नहीं रहना चाहिए।

लॉकडाउन फेल होने की आशंका पर मुखर हुए बिहार के मुख्यमंत्री पेज>>4

बिना हिस्ट्री वाले संक्रमित मरीजों ने बढ़ाई केंद्र सरकार की चिंता

नीतू रंजन, नई दिल्ली

बिना किसी हिस्ट्री के कोरोना मरीजों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। वैसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) का कहना है कि ऐसे मरीजों की संख्या बहुत कम है और स्थिति फिलहाल पूरी तरह नियंत्रण में है। इसके साथ ही आईसीएमआर ने एक बार फिर साफ किया कि देश में टेस्ट किट की कोई कमी नहीं है, लेकिन अभी मास टेस्ट की जरूरत नहीं है। वहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है।

आईसीएमआर के डॉ. रमन गंगाखेडकर ने स्वीकार किया कि सांस की गंभीर बीमारी से ग्रसित कुछ व्यक्तियों को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है, जिनकी विदेश यात्रा या फिर किसी कोरोना वायरस

आइसीएमआर ने कहा- संख्या बहुत कम, हिस्ट्री पता लगाने की हो रही कोशिश

से ग्रसित व्यक्तियों के संपर्क में आने की हिस्ट्री नहीं है। लेकिन उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि उनकी संख्या बहुत ही कम है और इसे कम्प्यूटरी ट्रांसमिशन का मामला फिलहाल पूरी तरह नियंत्रण में है। इसके अनुसार, संचारी रोगों में कई बार लोगों को अपनी हिस्ट्री छिपाते हुए देखा गया है। कोरोना के मामले में भी कुछ ऐसे केस आए हैं जो जरूरत नहीं हैं। वहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है।

आईसीएमआर के डॉ. रमन गंगाखेडकर ने स्वीकार किया कि सांस की गंभीर बीमारी से ग्रसित कुछ व्यक्तियों को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है, जिनकी विदेश यात्रा या फिर किसी कोरोना वायरस से पांच लाख किट आ गए हैं। उन्होंने

बताया कि सरकारी लैब में 12 हजार हर दिन जांच की क्षमता है, लेकिन इसके 30 फीसद का ही इस्तेमाल हो रहा है। वहीं निजी लैब में जांच शुरू हो गई है और अब तक 440 लोग वहां जांच करा चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिस किसी को भी जांच की जरूरत पड़ रही है, जांच की जा रही है। फिलहाल मास टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने देश में फिलहाल व्वाइरटाइन ऑफ केंचर टेस्ट (घर में ही टेस्ट कराने की सुविधा) की इजाजत देने से भी इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वायरस से ग्रसित होने के बाद भी इसकी जानकारी किसी को नहीं देंगे और यह खतरनाक हो सकता है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर इस पर बाद में विचार किया जा सकता है।

हॉटस्पॉट पर विशेष नजर पेज>>5

मिसाल

समाज को राह दिखाने वाला है हिमाचल के शोकाकुल माता-पिता का यह फैसला, कुल्लू जिला निवासी 25 साल के रोबिन की 12 दिन पहले हो चुकी थी मौत, आज है तेरहवीं, दो हजार लोगों को मास्क बांटेंगे माता-पिता

तेरहवीं पर भोज की जगह दान करेंगे मास्क

जीना इसी का नाम है

दिवेंद्र गकुर, कुल्लू

संकट के समय में थोड़ा सा विवेक, थोड़ा सा साहस किस प्रकार रूढ़ियों को तोड़ कर नई इबारत लिखता है, इसकी मिसाल बने हैं हिमाचल प्रदेश के गुमान सिंह। पर्यावरणविद एवं हिमालय नीति अभियान के संयोजक गुमान सिंह और उनकी पत्नी समाजसेविका हरा देवी अपने 25 वर्षीय पुत्र रोबिन की मृत्यु के सदमे से जुड़ रहे हैं। लेकिन वह रविवार, 29 मार्च को रोबिन की तेरहवीं की रस्म, भोज इत्यादि करने के बजाय कोरोना के खिलाफ जंग में शामिल होंगे और 2000 मास्क बांटेंगे।

मेरा बेटा असमय चला गया। उसकी तेरहवीं पर खर्च होने वाला पैसा महिला मंडलों व स्वयं सहायता समूहों को दो हजार मास्क बनाने के लिए दे दिया है। बंजार क्षेत्र की दूरदराज पंचायतों गाड़ागुशीणी, खौली, वलीधार और पलाह कलवारी, खुंदन, देहरी, सिधवां आदि गांव में मास्क नहीं मिल रहे हैं। हिमालय नीति अभियान के सदस्य 29 मार्च को इन जगहों पर लोगों को मुफ्त मास्क बांटेंगे।

गुमान सिंह, रव. रोबिन के पिता

जुटनी थी और सामूहिक भोज भी होता। लेकिन इन्होंने देश पर कोरोना वायरस के संकट के मद्देनजर परंपरागत रस्मों और रिवाजों को नया मोड़ दे दिया। गुमान सिंह और हरा देवी के घर न कोई भीड़ जुटेगी और न कोई कार्यक्रम होगा। फैसला लिया कि तेरहवीं पर जो खर्च आना था, उसी से मास्क बनवाएंगे और 2000 लोगों को मुफ्त बांटेंगे। महिला मंडल व स्वयं सहायता समूह मास्क बनाने में जुटे हैं।



हिमालय नीति अभियान के संयोजक गुमान सिंह और उनकी पत्नी हरा देवी।

प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे 'मन की बात'

नई दिल्ली, आइएनएस : कोविड-19 महामारी को लेकर लागू देशव्यापी लॉकडाउन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर महीने रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम 'मन की बात' का प्रसारण रविवार को होने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने दिव्यतर पर रविवार को इसके लिए लोगों से विचार एवं सुझाव मांगे हैं।

मोदी ने ट्वीट किया है, 'इस महीने की 29 तारीख को 'मन की बात' का प्रसारण होगा। कार्यक्रम के लिए आपके सुझाव सुनकर बहुत खुशी होगी। अपना संदेश रिकॉर्ड करने के लिए 1800-11-7800 को डायल करें या फिर माइगोव और नमो एप पर विचार साझा करें।' अनुमान है कि मोदी कार्यक्रम में स्वास्थ्य, हाइजीन और कोरोना वायरस पर देश की लड़ाई पर बात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक पीएम 'मन की बात' को कोरोना वायरस योद्धाओं को समर्पित कर सकते हैं। इन योद्धाओं में डॉक्टर, नर्स और पुलिसकर्मी आदि शामिल हैं।

बिजली ग्राहकों को भी राहत देने की तैयारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कोरोना से जिस तरह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है उससे आम जनता को बिजली बिल के भुगतान से भी राहत मिलने की संभावना है। केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से बिजली उत्पादक कंपनियों को निर्देश दे दिया है कि अगर राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) तीन महीनों तक भुगतान नहीं कर सकती हैं तो उन पर जुर्माना नहीं लगाया जाए।

साथ ही राज्यों से कहा गया है कि वे डिस्कॉम से निर्देश दें कि अगर बिजली उपभोक्ता मार्च से मई, 2020 तक अपने बिल का भुगतान नहीं कर पाते हैं तो उन पर पेनाल्टी नहीं लगाएंगे। इस बारे में अंतिम फैसला राज्य सरकारों अपने बिजली नियामक प्राधिकरणों से विमर्श वार्डन पर देश की लड़ाई पर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि अपनी हिस्ट्री नहीं बताने वाले मरीजों की जांच की जा रही है कि उन्हें यह वायरस कहाँ से मिला।

केंद्र सरकार ने राज्यों को दिया सुझाव- तीन महीने बिल अदायगी नहीं होने पर भी ग्राहकों पर नहीं लगाए जुर्माना

नहीं मिला पाएगा इसलिए मौजूदा नियमों में बदलाव जा रहा है ताकि बिजली आपूर्ति में कोई समस्या न हो। पहला बदलाव यह किया जा रहा है कि पहले के आपूर्ति का भुगतान नहीं होने के बावजूद डिस्कॉम को बिजली दी जाती रहेगी। इस बारे में बिजली कंपनियों को कहा गया है कि कोई डिस्कॉम भुगतान भी नहीं कर पा रही है तब भी उसे पर्याप्त बिजली आपूर्ति की जाएगी। पेंमेंट सेक्योरिटी व्यवस्था के तहत पहले किए जाने वाले भुगतान की राशि भी 50 फीसद घटाई जा रही है। साथ ही राज्यों से कहा गया है कि वे डिस्कॉम को निर्देश दें कि अगर कोई ग्राहक समय पर भुगतान नहीं कर पाता है तो उस पर ज्यादा पेनाल्टी न लगाएंगे।

राज्य सरकारें करेंगी फैसला, किसे देनी है कितनी राहत पेज>>5